

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1284  
30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपड़ा उद्योग की स्थापना

1284. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधे कंपनियों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सूती कपड़ा उद्योग स्थापित किए हैं, जिससे किसानों को उनकी कपास उपज का उचित मूल्य मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार का यवतमाल जिले में यथाशीघ्र कपड़ा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है?

उत्तर  
वस्त्र राज्य मंत्री  
(श्री पबित्र मार्घेरिता)

(क): कपास का बाजार मूल्य एमएसपी दरों से कम होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा कपास के एमएसपी अभियान के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे मामलों में, सीसीआई कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) यार्ड में, बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कपास किसानों से सीधे कपास खरीदता है। सीसीआई की अखिल भारतीय स्तर पर पर्याप्त अवसंरचना है अर्थात् कपास किसानों के हितों की रक्षा के लिए 145 जिलों में 17 शाखाएँ और 450 से अधिक खरीद केंद्र हैं।

(ख): यवतमाल जिले में कपास का बाजार मूल्य एमएसपी दर से कम होने पर, कपास किसानों की सहायता के लिए सीसीआई ने अपने शाखा कार्यालय अकोला के अंतर्गत आठ खरीद केंद्र खोले हैं। कपास मौसम वर्ष 2023-24 के दौरान, सीसीआई ने यवतमाल जिले में 71.79 करोड़ रुपये मूल्य की 20,730 गांठें खरीदी हैं, जिससे 4,872 किसान लाभान्वित हुए हैं। यवतमाल जिले में कपास की केंद्र-वार खरीद नीचे दी गई है:

खरीद केंद्र	कपास की खरीद (गांठों में)	खरीद का मूल्य (करोड़ रुपए में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
दरवहा	4,835	16.81	1,066
दिग्रस	738	2.46	165
घाटंजी	1,498	5.28	370
खैरी	931	3.21	245
पंडारकौड	1,759	6.05	413
रालेगांव	580	2.06	169
वानी	10,389	35.92	2,444
कुल	20,730	71.79	4,872

\*\*\*